झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविद याचिका संख्या 2942/2023

1. राम कृपाल राम, उम्र लगभग 71 वर्ष, पुरुष, पिता-श्री राम
2. मीना देवी, उम्र लगभग 65 वर्ष, पति- राम कृपाल राम, दोनों निवासी मोहल्ला-बागेश्वरी कॉलोनी, डाकघर और थाना- डेल्हा, जिला-गया (बिहार)

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. राधा कुमारी उर्फ़ कुमारी राधा, उम्र लगभग 24 वर्ष, पति- अमरेश प्रकाश, पिता- श्री नरेश सिंह, निवासी गोधर नंबर 6, सामुदायिक भवन के पास केंदुआडीह, कुसुंडा, थाना- केंदुआडीह जिला-धनबाद (झारखंड)

..... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए:	मोहम्मद फारूक अंसारी, एडवोकेट।
राज्य के लिए:	सुश्री वंदना भारती, अतिरिक्त पीपी
ओ.पी. नंबर 2 के लिए:	श्री अभिजीत कुमार सिंह, एडवोकेट।
	श्री शैलेश कुमार सिंह, एडवोकेट।

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षकारों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें दिनांक 02.05.2023 (अनुलग्नक - 1) का संज्ञान लेते हुए आदेश और विद्वान जे.एम.एफ.सी द्वारा पारित शिकायत केस संख्या 13362/2022 से उत्पन्न पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने

की प्रार्थना की गई है। धनबाद जिसके तहत और जहां के तहत, विद्वान जे.एम.एफ.सी धनबाद ने दिनांक 02.05.2023 के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए, 323 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता नंबर 1, ससुर होने के नाते और याचिकाकर्ता नंबर 2 सास होने के नाते, शिकायतकर्ता की शादी उनके बेटे के साथ होने के बाद, 04.07.2020 को, शिकायतकर्ता के साथ उसके पिता के घर गई और शिकायतकर्ता के पिता से 20,00,000/- रुपये दहेज की मांग की, लेकिन जैसा कि उक्त दहेज की मांग है, शिकायतकर्ता के पिता से मुलाकात नहीं की जा सकी, अन्य बातों के साथ-साथ, याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता की और याचिकाकर्ता नंबर 2 ने शिकायतकर्ता के गहने छीन लिए और 15.10.2022 को याचिकाकर्ताओं ने सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। ट्रायल कोर्ट के एक सवाल के जवाब में, शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता और उसका पति, दहेज की मांग कर रहे थे और याचिकाकर्ता और सह-आरोपी व्यक्ति, दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ मारपीट करते थे और उसकी शादी के बाद, याचिकाकर्ता और उसका पति, 20,00,000/- रुपये के दहेज की मांग करते थे। यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता पीड़िता को यह कहकर ताना मारते थे कि उसे फाइलेरिया है लेकिन उसे कभी मेडिकल चेकअप के लिए नहीं ले गए।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। शिकायतकर्ता पक्ष नंबर 2 ने यह मामला तब दर्ज किया जब उसे पता चला कि उसके पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव के लिए याचिका दायर की है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता पार्टी नंबर 2 ने कभी भी अपने पति के साथ अपना वैवाहिक जीवन बिताने की कोशिश नहीं की और वह अपने पति को अपने माता-पिता से अलग रहने के लिए जोर दे रही थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता लंबे समय से शिकायतकर्ता से अलग रह रहे हैं - विपक्ष पार्टी नंबर 2 लंबे समय से और शिकायतकर्ता -विपक्ष पार्टी नंबर 2 अपने माता-पिता के घर पर रह रही है।

5. **कहकशां कौसर उर्फ़ सोनम और अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। बनाम। **बिहार राज्य और अन्य। (2022) 6 SCC 599** में रिपोर्ट किया गया, जिसके पैरा 18 में निम्नानुसार पढ़ा गया है:

> "18. इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, 1-4-2019 की एफआईआर की सामग्री के अवलोकन पर, यह पता चलता है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सभी आरोपियों ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया और उसे गर्भपात कराने की धमकी दी। इसके अलावा, यहां अपीलकर्ताओं में से किसी के खिलाफ कोई विशिष्ट और अलग आरोप नहीं लगाए गए हैं, यानी अपीलकर्ताओं में से किसी को भी उनके खिलाफ लगाए गए सामान्य आरोपों को आगे बढ़ाने में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। यह बस एक ऐसी स्थिति की ओर जाता है जिसमें कोई अपराध को आगे बढ़ाने में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाने में विफल रहता है। इसलिए, आरोप सामान्य और सर्वव्यापी हैं और कहा जा सकता है कि छोटी झड़पों के कारण लगाए गए हैं। जहां तक पति का संबंध है, चूंकि उसने उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की है, हमने उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच नहीं की है। हालांकि, जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और सर्वव्यापी हैं, अभियोजन की आवश्यकता नहीं है।"

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप प्रकृति में सामान्य और सर्वव्यापी हैं और वे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी अभियोजन का वारंट नहीं करते हैं।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील आगे **प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य। (2010) 7 एससीसी 667** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। जिसमें उस मामले के तथ्यों में, जहां भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ताओं को आपराधिक मुकदमे की कठोरता से गुजरने के लिए मजबूर करना अनुचित होगा और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

के समक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को रद्द कर दिया, सामान्य ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में वैवाहिक मुकदमेबाजी तेजी से बढ़ रही है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील **मोहम्मद इम्तियाज सिद्दीकी उर्फ़ मोहम्मद इम्तियाज सिधीकी और अन्य बनाम। झारखंड राज्य और अन्य। संबद्ध मामले, सीआरएमपी संख्या 3413/2021 दिनांक 09.08.2023** के सम्बन्ध मामले में पारित इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। जिसमें उस मामले के तथ्यों में, जहां इस न्यायालय के समक्ष सी.आर.एम.पी संख्या 3413 / 2021 के याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति का था और उनके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, इस न्यायालय का विचार था कि उक्त सीआरएमपी संख्या 3413 / 2021 के याचिकाकर्ता की आपराधिक कार्यवाही जारी है, यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील **संजीव कुमार और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य। सीआरएमपी संख्या 1094/2016** के मामले में पारित किया गया, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा करते हैं। जिसमें उस मामले के तथ्यों में समन्वय पीठ, जब उस मामले के याचिकाकर्ता नंबर 2 से 7 के खिलाफ आरोप, प्रकृति में सामान्य और सर्वव्यापी थे, याचिकाकर्ता संख्या 2 से 7 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ संज्ञान लेने का आदेश दिनांक 02.05.2023 को विद्वान जे.एम.एफ.सी धनबाद द्वारा पारित किया गया था शिकायत मामला संख्या 1 के साथ। (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं 13362 / 2022 को रद्द किया जाए और अलग रखा गया।.

9. दूसरी ओर, विद्वान अपर पीपी और विपक्षी पार्टी नंबर 2 के विद्वान वकील, पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ-साथ शिकायत केस नंबर 13362 / 2022 के संबंध में विद्वान जे.एम.एफ.सी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 02.05.2023 के आदेश का जोरदार विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है, 04.07.2020 को 20,00,000/- रुपये दहेज की मांग करने और उसके बाद निरंतर अवधि के लिए, दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए शिकायतकर्ता के साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता दोनों के साथ व्यवहार करने के

बाद और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भी विशिष्ट आरोप है कि 15.10.2022 को, जब याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ बेरहमी से शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया, जिसने शिकायतकर्ता को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया और प्रस्तुत किया कि, चूंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप हैं, इसलिए, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए मामलों के तथ्य, इस मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग हैं, उन मामलों का अनुपात इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के खारिज कर दी जाए।

10. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 04.07.2020 को शिकायतकर्ता के पिता से बिना किसी अनिश्चित तरीके के 20,00,000/- रुपये दहेज की मांग करने का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है और आगे आरोप है कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के साथ मानसिक और मानसिक व्यवहार करते थे उसके बाद दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए शारीरिक क्रूरता, और याचिकाकर्ता नंबर 2 के खिलाफ शिकायतकर्ता के गहने ले जाने का भी विशिष्ट आरोप है। इसके अलावा, विशिष्ट आरोप है कि 15.10.2022 को, याचिकाकर्ताओं ने सह-अभियुक्त के साथ, शिकायतकर्ता के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसे चोट लगी और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया और यह याचिकाकर्ताओं का स्वीकृत मामला है कि शिकायतकर्ता अपने माता-पिता के घर में रह रही है।

11. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 04.07.2020 और 15.10.2022 और अन्य अलग-अलग तारीखों की घटनाओं के प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप हैं, क्रूरता करने और 20,00,000/- रुपये के दहेज की मांग करने के कारण, इस न्यायालय का विचार है कि इस मामले के तथ्य मामलों के तथ्यों से पूरी तरह से अलग हैं- जिनके निर्णय, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा इस पर भरोसा किया गया है, इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है, जहां पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ दिनांक 02.05.2023 को संज्ञान लेने का आदेश विद्वान जे.एम.एफ.सी. धनबाद द्वारा शिकायत केस संख्या 202 के संबंध में पारित किया गया

था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं 13362 / 2022 को रद्द किया जाए और अलग रखा गया।.

12. तदनुसार, इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 6 मार्च, 2024
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद सुश्री मधु कुमारी
पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।